श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2012 को समाहरणालय सभाकक्ष में सम्पन्न भू-अभिलेख कम्प्युटरीकरण योजनान्तर्गत भू-अभिलेखों का कम्प्युटराईजेशन से संबंधित बैठक की कार्यवाही :-

---

1. उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

2. परिचय :-

जिला के उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी/अमीन को भू-अभिलेख कम्प्युटराईजेशन से संबंधित सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निदेश से अवगत कराया गया कि कृषि रोड मैप के अन्तर्गत भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंचल स्तर पर अद्यतन चालू खतियान का निर्माण तथा कम्प्युटर के माध्यम से संधारण करते हुए रैयतों को चालू खतियान की अद्यतन कम्प्युटराईज्ड प्रति उपलब्ध कराना है। इस निमित्त निरन्तर विभागीय दिशा-निदेश/मार्गदर्शन की प्रति विभाग से प्राप्त होने पर आप सबों को उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा समीक्षात्मक बैठकों में इस योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य के जिलों की भौतिक उपलब्धि की लगातार समीक्षा की जा रही है जिसके फलस्वरूप समीक्षा के क्रम में जिलों की न्युनतम उपलब्धि के प्रति सरकार द्वारा गहरा असंतोष व्यक्त किया गया है। आप अवगत हैं कि किसी योजना विशेष के अन्तर्गत लक्ष्य की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब क्षेत्रीय स्तर पर सघन अभियान के तहत् कार्रवाई की जाए। क्षेत्रीय स्तर से की जानेवाली कार्रवाई के संबंध में दिशा-निर्देश/मार्गदर्शन पूर्व में आपको प्रेषित की गयी है।

3. अंचल स्तर पर खेसरापंजी, जमाबंदी पंजी ॥ :-

अंचल स्तर पर खेसरा पंजी, जमाबंदी पंजी ॥ का अद्यतन रूप में संधारण के पश्चात बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुरूप चालू खतियान कां संधारण किया जाना आवश्यक है। चालू खतियान के निर्माण में दाखिल खारीज का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना आप सबों को जिला राजस्व कार्यालय के पत्रांक 390/रा0 दिनांक 03.08.2012 के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। कार्ययोजना के तहत निर्धारित अवधि के अन्दर भू-अभिलेख कम्प्युटरीकरण का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में कार्य पूरा नहीं होने पर आप सबों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आप अवगत हैं कि मुंगेर जिला का आधुनिक तकनीक से भू-खंडों का डिजिटल सर्वे मानचित्र तैयार कर ली गयी है। उम्मीद की जाती है कि 15-20 दिनों में मानचित्र जिला को उपलब्ध हो जाएगा।